हिंदी सांध्य दैनिक

भवानी टाईम्स

प्रधान संपादक : चंद्रकांत खंडेलवाल, 9422831140 | RNI Reg.NO.39851/1981 | E-mail : bhawanitimes@gmail.com | संपादक : प्रदिप शेंडे, 9823924676

वर्ष : 46 | अंक : 81 | गोंदिया, सोमवार दि. 24 अगस्त 2026 | पृष्ठ : 04 | मूल्य : 1.10 रू | Post Redg.NPMFL/27/2024-2026

मार्ग पर खड़े रहकर बस का इंतजार

सालेकसा : बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों को बारिश से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं है. सबसे जरूरी यात्री प्रतीक्षालय की सुविधा ही नहीं है और बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सड़क पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते देखे जा रहे हैं. इतने वर्ष बाद भी बस स्टैंड उपलब्ध नहीं होने से आदिवासी व आम नागरिकों को सड़क पर खड़े रहकर बस या अन्य साधनों का इंतजार करना पड़ता है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड का निर्माण करने की मांग की गई है.

संक्षिप्त

सड़कों की चौड़ाई बढ़ाए जाने की मांग

गोरेगांव : ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों की ओर जाने वाली सड़कें बहुत संकरी हैं. जिससे इन सड़कों पर आने-जाने वाले नागरिकों और वाहन चालकों को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसके साथ ही कई लोग छोटे-बड़े हादसों का सामना कर रहे हैं. संबंधित विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों का चौड़ीकरण करें, ऐसी मांग की जा रही हैं.

तबीयत बिगड़ने से व्यक्ति की मौत

गोंदिया : गोरेगांव थाने के तहत मोहाड़ी निवासी भीमराज सुरजलाल बिसेन (50) की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उसे ग्रामीण अस्पताल गोरेगांव ले जाया गया. जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. गोरेगांव पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार कुरसुंगे कर रहे हैं.

ट्रक से गिरने से व्यक्ति की मौत

गोंदिया : डुग्गीपार थाने के तहत ग्राम सावंगी में ट्रक से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, गुजरात के आनंद जिले के बोरसद निवासी हसमुख भाई जिवा भाई रोहीत (49) रायगड से सेनागपुर की ट्रक से जा रहा था. इसी बीच महाराष्ट्र के सावंगी जिप स्कूल के सामने वह ट्रक से गिर गया. उसे ग्रामीण अस्पताल सड़क अर्जुनी में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. फिर्यादी नागजी भाई चरण भाई रबारी (60) की शिकायत पर डुग्गीपार पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है.

लोहे की रॉड से युवक पर किया अचानक प्रहार

गोंदिया : शहर थाने के तहत चांदनी चौक में फुलचूर पे' निवासी फिर्यादी अभिषेक सुभाष राऊत (23) खड़ा था. इस दौरान सावराटोली निवासी आरोपी उदय (20) व अन्य दो युवक मोटरसाइकिल से आए व सा'गां' कर फिर्यादी को तु ज्यादा गरम दे रहा है क्या, ऐसे कहते हुए गालीगलौज की व उदय ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर प्रहार कर दिया. वहीं अन्य आरोपियों ने लात-घुसों से मारपीट की.

स्पीड ब्रेकर बन रहे हादसों की वजह

गोंदिया : स्पीड ब्रेकर हादसों में कमी लाने के लिए सड़कों पर बनाए जाते हैं लेकिन अगर यह स्पीड ब्रेकर औसत से ऊंचा हो तो यह हादसों का भी सबब बन जाता है. शहर में कई ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जो औसत से ऊंचे हैं.

२१५ से अधिक हादसों में ११४ लोग हो चुके हैं गंभीर घायल

जर्जर सड़कों पर १२४ लोगों की मौत

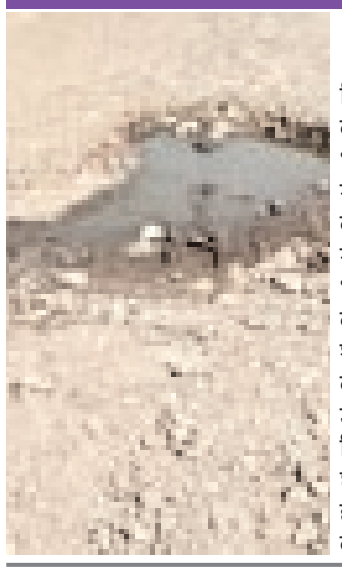

संवाददाता / गोंदिया

जिले में सड़कों की बदहाल स्थिति और घटिया निर्माण कार्य अब लोगों की जान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है. महज छह महीने पहले तैयार की गई सड़कें पहली ही बारिश में बहने लगी हैं, तो जिले में हुए भारी बारिश ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी है. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई सड़कें और मार्ग अब मौत के जाल में तब्दील होते जा रहे हैं. पिछले आठ महीनों में जिले में छोटे-बड़े 215 से अधिक सड़क हादसे सामने आए हैं. इन दुर्घटनाओं में 124 लोगों की मौत, जबकि 114 लोग गंभीर और 42 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. कई घायलों को स्थायी अपंगता का सामना करना पड़ा है. इसके बावजूद हादसों को रोकने के लिए ठोस व प्रभावी उपाय नहीं होने से दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति और भी खराब है. सड़क निर्माण के लिए शासन द्वारा करोड़ों रु. का निधि उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, काम में पारदर्शिता और समय पर रखरखाव की अनदेखी का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है. सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास का आईना मानी जाती हैं. लेकिन जिले में सड़कों की मौजूदा स्थिति विकास के दावों पर ही सवाल खड़े कर रही है. सड़क निर्माण में अनियमितता, घटिया सामग्री के इस्तेमाल और कमीशनखोरी की चर्चाओं के चलते निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होने की बात भी सामने आ रही है.

जर्जर पुलों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे

सालेकसा, अर्जुनी मोरगांव, देवरी और आमगांव तहसील के प्रमुख मार्गों पर स्थित कई पुलों व सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है. इनमें कुछ पुल पुराने होकर जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं, जबकि कई मार्ग भी खस्ताहाल हैं. इन सड़कों व पुलों की देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व जिला परिषद के निर्माण विभाग की है. जर्जर पुलों का समय-समय पर स्ट्रक्चरल ऑडिट कर उनकी सुरक्षा जांचना बेहद जरूरी है. हालांकि, जिले में अब तक कितने पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया, इसकी स्पष्ट जानकारी संबंधित विभागों के पास उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है. अब विभागों की ओर से जल्द स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की बात कही जा रही है.

548 ग्राम पंचायतों पर सरकार की नजर

संवाददाता / गोंदिया

ग्राम पंचायतों के कामकाज में अनुशासन व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अब ग्राम पंचायत अधिकारियों, लिपिकों और परिचरों की उपस्थिति बायोमेट्रिक व जीपीएस प्रणाली के माध्यम से दर्ज करने की तैयारी तेज हो गई है. महाराष्ट्र शासन के ग्राम विकास विभाग ने इस संबंध में 18 अगस्त को राज्य की सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दोबारा निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के बाद गोंदिया जिले की 548 ग्राम पंचायतों में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. शासन के इस निर्णय से कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से होने की उम्मीद है. ग्राम विकास विभाग के कार्यासन अधिकारी नितीन पवार द्वारा जारी पत्र में ग्राम पंचायत अधिकारियों, जिन्हें पहले ग्रामसेवक अथवा ग्रामविकास अधिकारी के नाम से जाना जाता था, की बायोमेट्रिक व उझर आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में शासन ने इससे पहले 10 दिसंबर 2024 को भी पत्र जारी किया था.

गोस्वामी तुलसीदास महाराज जयंती मनाई

संवाददाता / गोंदिया

श्री राम चेतना केंद्र गौरक्षा आश्रम में महान संत कवि संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई. विगत 30 वर्षों से गोस्वामी तुलसीदास जयंती संस्थापक गणेश प्रसाद राय द्वारा शुरुआत की गई और निरंतर धार्मिक कार्य और गौ सेवा निरंतर शुरू है. इस कार्यक्रम में हनुमान चालीसा पा' और तुलसीदास के दोहे चौपाई सुनाई गई.

अध्यक्ष अजयसिंह गौर, उपाध्यक्ष नरसिंह गहरवार गौरीशंकर राय, हरीश गुप्ता, गौरव लांजेवार, प्रणव लांजेवार, सोहन देखनवार, श्रीचंद मड़ावी, गुप्ता, अनीता आदि उपस्थित थे. अंत में एड. रमाशंकर राय और गजानन राय ने सभी गौ भक्तों का आभार प्रदर्शन किया.

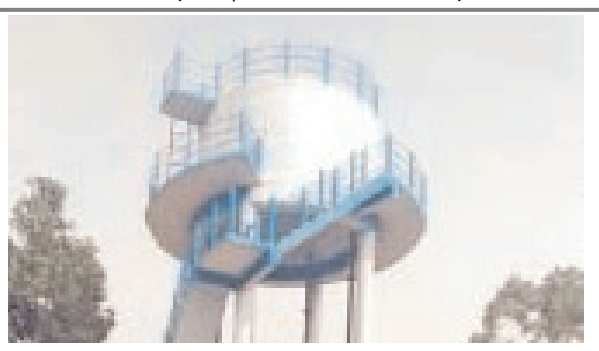

३ वर्ष से जल जीवन के काम अधूरे

जल्द राशि उपलब्ध कराने एवं कार्य शुरु करने की मांग

संवाददाता / दरेकसा

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरु किए गए कार्य पिछले करीब तीन वर्षों से अधूरे पड़े हैं. कई स्थानों पर ठेकेदार आधे-अधूरे काम छोड़कर चले गए हैं. इससे ग्रामीणों को योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है.

सालेकसा तहसील के मुरकुटडोह, बंजारी और जमाकुडो समेत विभिन्न गांवों में जल जीवन मिशन के कार्य लंबे समय से अधूरे हैं. कहीं पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है तो कहीं जलापूर्ति से संबंधित अन्य आवश्यक कार्य पूरे नहीं हुए हैं. ऐसे में 'हर घर जल' योजना का उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है. जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा करीब एक वर्ष पहले जानकारी दी गई थी कि जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार से 50 करोड़ रु. की मांग की गई थी, लेकिन इसके मुकाबले सिर्फ 8 करोड़ रु. की निधि प्राप्त हुई. सीमित निधि के कारण सभी कार्यों को समय पर पूरा करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है. उपलब्ध राशि को विभिन्न कार्यों में किस प्रकार वितरित किया जाए, यह भी विभाग के सामने चुनौती बनी हुई है.

योजना के कार्य अधूरे रहने के कारण ग्रामीण आज भी बोरवेल, कुएं और अन्य पारंपरिक जलस्रोतों पर निर्भर हैं. गर्मी के दिनों के साथ बारिश के मौसम में भी कई स्थानों पर पेयजल की समस्या गंभीर हो जाती है.

२७ अगस्त को विकसित भारत युवा कनेक्ट का आयोजन

पीएम मोदी करेंगे युवाओं को संबोधित

संवाददाता / गोंदिया

राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में देशभर में आयोजित होने वाले 'विकसित भारत युवा कनेक्ट-स्पोर्ट्स एडिशन' के तहत 27 अगस्त को नटवरलाल माणिकलाल दलाल महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम का आयोजन गोंदिया शिक्षण संस्था के माननीय प्रफुल भाईजी पटेल, आदरणीय वर्षा ताई पटेल, सन्माननीय राजेंद्र जी जैन एवं माननीय निखिल जी जैन के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री देशभर की करीब 1600 लोकेशनों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं को एक साझा मंच से संबोधित करेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं, खिलाड़ियों और भारत के भविष्य को एक मंच पर लाना है।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद महाविद्यालय परिसर में स्थानीय युवा संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें MY Bharat स्वयंसेवकों और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच खेल बुनियादी ढांचे तथा देश में विकसित हो रहे खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा होगी। 15 मिनट के विशेष संवाद में विद्यार्थियों को अपने विचार, सुझाव और भविष्य की आकांक्षाएं साझा करने का अवसर मिलेगा।

महाविद्यालय प्रशासन ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं से सुबह 10 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहने की अपील की है।

सालेकसा के 5 गांवों में आज भी श्मशान भूमि नहीं

बरसात में खुले में करना पड़ रहा शवदाह

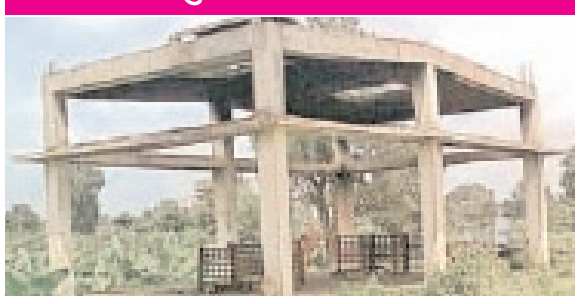

संवाददाता / सालेकसा

नगर पंचायत सालेकसा क्षेत्र के पांच गांवों में आज भी श्मशानभूमि की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों को किसी की मृत्यु होने पर नाले किनारे या जंगल जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है. बरसात में खुले स्थान पर शवदाह करना ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है. नगर पंचायत क्षेत्र के आमगांव खुर्द को छोड़कर सालेकसा, हलबीटोला, मुरुमटोला, जांभली और बाकलसरा गांवों में गांव के अधिकार की श्मशानभूमि नहीं है. हलबीटोला गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए शव को करीब तीन से चार किलोमीटर दूर जांभली नाले के पास ले जाना पड़ता है. दौरान अंतिम यात्रा के रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग आती है. व्यस्त रेलवे लाइन होने के कारण कई बार रेलवे गेट बंद रहता है, जिससे ट्रेन गुजरने का इंतजार करना पड़ता है. नाले के किनारे अंतिम संस्कार के दौरान अचानक बारिश शुरू हो जाए तो स्थिति और गंभीर हो जाती है. श्मशानभूमि और शेड की सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. वहीं सालेकसा (पुराना), मुरुमटोला और जांभली के ग्रामीणों को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बाकलसर्रा के लोगों को जंगल में जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत की स्थापना को करीब 15 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद श्मशानभूमि जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है. इस संबंध में गांव के युवाओं ने पहल करते हुए पांच वर्ष पहले मोक्षधाम सेवा समिति का गठन किया. समिति के सदस्य प्रत्येक रविवार श्रमदान कर अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं.

बांस की अनुपलब्धता से बेरोजगारी

अर्जुनी मोरगांव : बुरड़ समाज व मजदूरों की स्थिति दयनीय है. सरकार ने समय-समय पर कानून पारित किए लेकिन वे सारे कानून धरे के धरे रह गए. वन विभाग की ओर से कम कीमत में मिलने वाला बांस मिलना बंद हो गया है. सवाल यह है कि ऐसे में जीवन कैसे जिया जाए. बुरड़ मजदूरों का जीवन बांस पर ही टिका है. प्लास्टिक के युग में बांस के उत्पादों की ज्यादा मांग नहीं है. लेकिन कुछ बांस उत्पाद घरेलू सामान के रूप में आवश्यक हो गए हैं.

१७,७२६ अपात्रों का राशन बंद

3.14 लाख राशन कार्डधारकों की जांच 'मिशन सुधार' का असर

संवाददाता / गोंदिया

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभार्थियों पर लगाम कसने के लिए राज्य में 'मिशन सुधार अभियान' तेजी से चलाया जा रहा है. अभियान के तहत आधार डेटाबेस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जानकारी के आधार पर संदिग्ध व फर्जी राशन कार्डों की गहन जांच की जा रही है. गोंदिया जिले में अब तक 17 हजार 726 अपात्र लाभार्थियों का राशन पूरी तरह बंद किया जा चुका है. वहीं, अभी भी हजारों लाभार्थी जांच के दायरे में हैं. केंद्र सरकार की ओर से आधार क्रमांक व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपलब्ध जानकारी के आधार पर जिलानिहाय संदिग्ध लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है. इसके आधार पर - आपूर्ति निरीक्षकों द्वारा घर-घर जाकर जांच की जा रही है. संबंधित लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने का अंतिम अधिकार तहसीलदारों को दिया गया है. जिले में कुल 3 लाख 14 हजार 645 राशन कार्डधारकों की जांच की जा रही है. अब तक जिन लाभार्थियों की जांच पूरी हो चुकी है, उनमें से 17 हजार 726 लाभार्थियों को अपात्र पाए जाने के बाद उनका राशन बंद कर दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, 'मिशन सुधार अभियान' का उद्देश्य केवल वास्तविक जरूरतमंद व पात्र लाभार्थियों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ सुनिश्चित करना है. हालांकि, तकनीकी कारणों से कुछ पात्र लाभार्थियों के नाम भी सूची से हटने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे नागरिकों में चिंता है.

कवडीमोल भावात जमीन संपादनामुळे शेतकरी आक्रमक

गुदमा-प्रतापबाग रेल्वे लाइन ; बाजारभावापेक्षा 5 पट अधिक नुकसानभरपाई द्या

संवाददाता / गोंदिया

गुदमा ते प्रतापबाग दरम्यान प्रस्तावित नव्या रेल्वे लाइनच्या निर्मितीसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू होताच संपूर्ण क्षेत्रात तीव्र जनआक्रोश उसळला आहे. कटंगी कला, नागरा, हलबीटोला आणि सावरी परिसरातील शेतकरी, प्लॉट, घर आणि दुकान मालकांना शासनाकडून मिळालेल्या नुकसान भरपाईच्या पत्रांमुळे नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ज्या जमिनीचे बाजारमूल्य कोट्यवधीच्या घरात आहे, ती जमीन रेल्वे प्रशासन व शासन कवडीमोल भावात हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप गावकरी व शेतकऱ्यांनी केला आहे. बाजारभावानुसार 5 पट मोबदला द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

गुदमा-प्रतापबाग रेल्वे लाइन प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासाठी परिसरातील गावात जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. ज्या शेतकरी व गावकऱ्यांच्या जमिनी या प्रक्रियेत जात आहेत, अशांना प्रशासन-शासनाकडून मोबदल्याच्या नोटिस पाठविण्यात आल्या. नोटीस पाहून एकच गोंधळ उडाला आहे. कोट्यवधी रुपये मूल्यांच्या जमिनीला शासन कवडीमोल भाव देत आहे, यामुळे गावकरी व शेतकऱ्यांमध्ये एकच आक्रोश निर्माण झाला आहे. या प्रशासकीय धोरणाच्या विरोधात रविवारी (ता.23) कटंगी कला येथील ग्रामपंचायत सभागृहात बाधित शेतकऱ्यांची तातडीची बैठक पार पडली. बैठकीत अपुऱ्या मोबदल्याबाबत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. अन्यायी दरावर कोणत्याही परिस्थितीत जमीन दिली जाणार नाही आणि रेल्वेला जमीन हवी असल्यास ग्रामस्थांच्या अटी मान्य कराव्याच लागतील, असा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. बाधित भू-धारकाच्या कुटुंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी देण्यात यावी, जमीन व मालमत्तेचे मूल्यांकन सध्याच्या बाजारभावानुसार किमान 5 पट अधिक देण्यात यावे, ज्यांची अर्धी जमीन संपादित होत असून उर्वरित भाग निरुपयोगी ठरत आहे, त्या संपूर्ण जमिनीची भरपाई मिळावी, रेल्वे लाइनमुळे पारंपरिक पांदण रस्ते बंद होत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी रस्त्यांची व्यवस्था करून द्यावी, आदि मागण्या नागरा, कटंगीकला, हलबीटोला, सावरी गावातील नागरिकांनी केल्या आहेत. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेमुळे गावकरी व रेल्वे प्रशासनामध्ये वाद पेटण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत.

बैठकीला अखिलेश सेठ, नंदू बिसेन, कार्तिक चौहान, सूरज बावनकर, ईश्वर उपवंशी, माणिकचंद भगत, सुरेश तिवडे, कृष्णा बान्ते, रुपेश लिल्हारे, इमलाबाई लिल्हारे, हेमंत कुमार हनवते, राजू चन्नेकर, रवींद्र कुमार चिकलोंडे यांच्यासह शेकडो बाधित भूधारक उपस्थित होते.

संपादकीय

बदहाल सड़कें, लाचार जनता

शहर की सड़कों की दुर्दशा आज किसी से छिपी नहीं है. कभी 'धान की नगरी' के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला गोंदिया शहर आज गड्ढों, धूल और बदहाली का पर्याय बनकर रह गया है. शहर के मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी बस्तियों की गलियों तक, ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहाँ यात्रियों को राहत मिल सके. कहने को तो हर साल बुनियादी ढांचे के नाम पर, सड़कों के निर्माण और डामरीकरण के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की भारी-भरकम निधियां स्वीकृत की जाती हैं. कागजों पर बड़ी-बड़ी विकास योजनाओं के आंकड़े चमकाए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर हकीकत देखी जाती है, तो जनता के हाथ सिर्फ धूल, कीचड़ और जानलेवा गड्ढे ही लगते हैं. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़कों का यह हाल देखकर आज गोंदिया की आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को वोट देकर पछता रही है.

मानसून आते ही शहर की सड़कों के दावों की हवा निकल जाती है. पहली ही बारिश में सड़कें बह जाती हैं और बड़े-बड़े जानलेवा गड्ढे उभर आते हैं. बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने से यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि 'सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क'. वहीं, बारिश बीत जाने के बाद उड़ती धूल ने नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है. शहर के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, स्कूली बच्चों और मरीजों के लिए इन सड़कों पर एक किलोमीटर का सफर करना भी किसी यातना से कम नहीं है. गड्ढों के कारण आए दिन रीढ़ की हड्डी और जोड़ों की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इसके साथ ही, दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने और गंभीर रूप से घायल होने की घटनाएं रोज की बात बन चुकी हैं. वाहन चालकों को अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा गाड़ियों की मरम्मत और मेंटेनेंस पर खर्च करना पड़ रहा है.

सबसे चिंताजनक और शर्मनाक पहलू यह है कि जनता की इस विकराल समस्या पर शहर के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से मौन साधे बैठे हैं. चुनाव के समय बड़े-बड़े मंचों से गड्ढामुक्त सड़कों और स्मार्ट सिटी जैसी लुभावनी बातें करने वाले नेता आज जनता की चीख-पुकार सुनकर भी धृतराष्ट्र बने हुए हैं. नगर परिषद प्रशासन हो या लोक निर्माण विभाग (झेंऊ), ठेकेदारों के साथ उनकी सांठगांठ की बदबू अब साफ महसूस की जा सकती है. घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, डामरीकरण में मानकों की अनदेखी और निर्माण के नाम पर महज लीपापोती करना अब एक नियम बन चुका है. सड़क बनते ही कुछ ही महीनों में उखड़ जाती है, लेकिन न तो ठेकेदारों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और न ही उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है. आखिर जनता के टैक्स के पैसों की इस खुली लूट की जवाबदेही किसकी है? जनप्रतिनिधियों की यह संवेदनहीनता अब गोंदिया के नागरिकों के धैर्य की परीक्षा ले रही है. लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं है. जिस सड़क पर चलने के लिए नागरिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स चुकाते हैं, उस पर सुरक्षित चलने का अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए. जनप्रतिनिधियों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को यह भली-भांति समझ लेना चाहिए कि जनता का आक्रोश अब अंतिम चरण में है. यदि जल्द ही शहर की सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत नहीं की गई, घटिया काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई और बदहाल सड़कों को गड्ढामुक्त नहीं बनाया गया, तो जनता का यह शांत गुस्सा बहुत जल्द एक उग्र जन-आंदोलन का रूप लेकर सड़कों पर उतरेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.

17 में से 1 ग्रापं में OBC सरपंच पद आरक्षित

व्यवस्था : बल्लारपुर तहसील में सरपंच पदों का आरक्षण, फिर नाराजगी की संभावना

बल्लारपुर : राज्य निर्वाचन आयोग ने २३ जुलाई के पत्र के माध्यम से ५० प्रतिशत से अधिक आरक्षण वाले बल्लारपुर तहसील में सरपंच पदों के आरक्षण में संशोधन करने का निर्णय लिया है. इसके तहत आगामी ४ सितंबर को सरपंच पदों के लिए नए सिरे से आरक्षण की लॉटरी निकालने के निर्देश जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी वसुमना पंत ने दिए हैं. नए आरक्षण के अनुसार बल्लारपुर तहसील की १७ ग्राम पंचायतों में से केवल एक ग्राम पंचायत में नागरिकों के पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सरपंच पद आरक्षित रहेगा. इससे ओबीसी समुदाय में एक बार फिर तीव्र नाराजगी की संभावना जताई जा रही है. विशेष बात यह है कि ८ जुलाई २०२५ को हुई आरक्षण लॉटरी में पांच ग्राम पंचायतों में ओबीसी के लिए सरपंच पद आरक्षित किए गए थे.

बल्लारपुर तहसील में कुल १७ ग्राम पंचायतें हैं. गत वर्ष ८ जुलाई को हुई सरपंच पदों की आरक्षण लॉटरी में विसापुर (ओबीसी महिला), कलमना (ओबीसी महिला), नांदगांव (पोडे) (ओबीसी सामान्य), बामणी (दुधोली) (ओबीसी सामान्य) तथा पलसगांव (ओबीसी सामान्य) में सरपंच पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था. लेकिन अब नए सिरे से होने वाली आरक्षण लॉटरी में १७ में से केवल एक ग्राम पंचायत में ओबीसी सरपंच पद रहेगा. इससे निर्णायक संख्या में मौजूद ओबीसी समुदाय में नाराजगी के स्वर उठने की संभावना बढ़ गई है.

बल्लारपुर तहसील की कुल १७ ग्राम पंचायतों में नए आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी) के लिए ३, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए ४, नागरिकों के पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए केवल १ तथा सामान्य वर्ग के लिए ९ सरपंच पद आरक्षित रहेंगे. ओबीसी के लिए आरक्षित एकमात्र सरपंच पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा.

अब नागरिकों का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि विसापुर, कलमना, नांदगांव (पोडे), बामणी (दुधोली), पलसगांव, कवडजई, किन्ही, काटवली (बामणी), कोठारी और कोटीमक्ता में से किस ग्राम पंचायत में ओबीसी महिला के लिए सरपंच पद आरक्षित होता है. नए सिरे से होने वाली आरक्षण लॉटरी में एससी के ३, एसटी के ४, ओबीसी का केवल १ तथा सामान्य वर्ग के ९ सरपंच पद रहेंगे. इनमें एससी महिला के लिए २, एसटी महिला के लिए २, ओबीसी महिला के लिए १ तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए ४ पद आरक्षित होंगे. इस प्रकार कुल ९ सरपंच पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे.

पिछले वर्ष ऐसा था सरपंच पदों का आरक्षण

बल्लारपुर तहसील की १७ ग्राम पंचायतों में ८ जुलाई २०२५ को आरक्षण लॉटरी निकाली गई थी. उस समय ओबीसी वर्ग के लिए विसापुर, कलमना, नांदगांव (पोडे), बामणी (दुधोली) तथा पलसगांव में सरपंच पद आरक्षित थे. सामान्य वर्ग के लिए कवडजई, किन्ही, काटवली (बामणी), कोठारी और कोटीमक्ता ग्राम पंचायतों में सरपंच पद निर्धारित किए गए थे. अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए लावारी, मानोरा, हडस्ती और आमडी में सरपंच पद आरक्षित था. इसी प्रकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए इटोली, गिलबिली और दहेली ग्राम पंचायतों में सरपंच पद आरक्षित किए गए थे.

वाड़ी में गुप्ता पान शॉप पर पुलिस का छापा

१.१७ लाख का प्रतिबंधित माल जब्त

नागपुर : शहर में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और गुटखे की अवैध बिक्री के खिलाफ पुलिस आयुक्त की विशेष एस्कॉर्ट टीम ने वाड़ी पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है. अमरावती रोड स्थित एक पान शॉप और उसके गोदाम पर देर रात छापा मारकर पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकूजन्य पदार्थ जब्त किए हैं. इस मामले में पान शॉप संचालक को गिरफ्तार कर १ लाख १७ हजार ५०० रुपए का माल बरामद किया गया है. २२ अगस्त की रात करीब ११:१० बजे पुलिस आयुक्त की एस्कॉर्ट टीम गश्त पर थी. तभी उसे पुख्ता जानकारी मिली कि वाड़ी थाना क्षेत्र में अमरावती रोड, सब्जी मार्केट के पास स्थित गुप्ता बिल्डिंग में संचालित गुप्ता पान शॉप में प्रतिबंधित तंबाकू की अवैध बिक्री की जा रही है. ऐसे में एस्कॉर्ट टीम ने वाड़ी पुलिस के साथ पान टपरी और उससे जुड़े गोदाम में संयुक्त छापेमारी कर अमरावती रोड निवासी नीतेश गुप्ता (३८) को गिरफ्तार किया.

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक भगवान कोली, पुलिस उपनिरीक्षक उत्तम जायभाये, हवलदार विजय गिरी, आशिष गायधने तथा अमलदार अरषद शेख, मनोज निमकर, गायत्री लांजेवार ने की.

विमल, रजनीगंधा समेत कई ब्रांड्स का जखीरा मिला

तलाशी के दौरान आरोपी के ठिकाने से सरकार द्वारा प्रतिबंधित सुगंधित विमल बिग, रजनीगंधा, बाबा ब्लैक, राजश्री पान, सिग्नेचर, मिराज, पान पराग प्रीमियम और वी-१ सहित अन्य तंबाकू उत्पादों का बड़ा स्टॉक बरामद हुआ. आरोपी अपने फायदे के लिए देर रात तक दुकान खुली रखकर अवैध रूप से इन प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री कर रहा था. पुलिस ने मौके से १ लाख १७ हजार ५०० रुपए मूल्य का माल जब्त किया.

ऐसे में आरोपी नीतेश गुप्ता पर वाड़ी थाने में भारतीय न्याय संहिता तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम २००६ के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को जब्त माल के साथ आगे की कार्रवाई के लिए वाड़ी पुलिस के सुपुर्द किया गया है.

आरओबी के लिए ९० करोड़ आखिर मंजूर

पुलगांव : वर्धा-बडनेरा रेलवे मार्ग पर पुलगांव का रेलवे गेट क्रमांक ८० पिछले कई वर्षों से बंद होने के कारण नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इस स्थान पर करीब १५ वर्षों से रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा था, लेकिन धीमी गति के कारण यह समस्या थी. विधायक राजेश बकाने के प्रयासों से रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास के निर्माण के लिए करीब ९० करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.

रेलवे गेट बंद होने से विद्यार्थियों, व्यापारियों, कामगारों और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा था. इससे समय की बर्बादी के साथ यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो रही थी. शहर की बढ़ती आबादी और यातायात को देखते हुए विधायक बकाने ने इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए. परियोजना का क्रियान्वयन महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महारेल) के माध्यम से किया जाएगा. ओवरब्रिज और अंडरपास बनने से यातायात व्यवस्था सुचारु होने के साथ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध होगा.

बल्लारपुर में पानी के लिए हाहाकार, भटक रहे नागरिक

बल्लारपुर : बल्लारपुर शहर में पिछले कई दिनों से पेयजल और बिजली संकट गहराता जा रहा है. वाटर सप्लाई और महावितरण हर बार सिर्फ 'रिपेयर का काम चल रहा है' का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है. लेकिन इस रिपेयर के नाम पर जनता को पानी के लिए कई दिनों तक व रोजाना घंटों तक लाइट से वंचित रहना पड़ रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विधायक सुधीर मुनगंटीवार के विशेष प्रयासों से बल्लारपुर में 24 घंटे शुद्ध पानी मिले, इसके लिए करोड़ों रु. की जलापूर्ति योजना लाई गई.

शहर में नई पाइपलाइन बिछाई गई, बड़े-बड़े वाटर टैंक बनाए गए. पर करोड़ों रु. खर्च होने के बाद भी नतीजा शून्य है. आज भी नलों में पानी नहीं आ रहा है. इसके लिए अनेक पार्टी, संगठन व संस्था के माध्यम से आंदोलन कर ज्ञापन दिया जाता है. उस पर कोई सुनवाई नही होती है. इस संकट की सबसे ज्यादा मार गरीब और मध्यम वर्गीय जनता पर पड़ रही है. सुबह होते ही बस्तियों में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है. महिलाएं और बच्चे छोटे-छोटे बर्तन, डिब्बे और बाल्टियां लेकर जिसके घर बोरिंग है, उसके यहां दौड़ लगाते नजर आते हैं.

लोग अपना रोज का मजदूरी का काम छोड़कर सिर्फ पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. बिजली की आंख-मिचौली ने भी लोगों को बेहाल कर दिया है. बोरिंग होने के बाद भी लाइट नहीं होने से मोटर नहीं चल पा रही.

नागरिकों का कहना है कि यदि योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो करोड़ों रु. लगा कर क्या फायदा. प्रशासन ने जल्द नियमित जलापूर्ति और बिजली बहाल नहीं की तो जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

पुलिस से बचने के लिए भागा युवक कुएं में गिरा

मौत के बाद परिजनों ने थाने में दिया धरना

मोर्शी : मोर्शी तहसील के डोंगरयावली में गुरुवार, 20 अगस्त को जुए के अड्डे पर पुलिस के छापे के बाद भागते समय युवक सूरज चढोकार (33, डोंगरयावली) की कुएं में गिरकर मौत हो गई. इसके लिए छापा मारने वाले संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर परिजन, गांव की महिलाएं और पुरुष शनिवार, 22 अगस्त को मोर्शी पुलिस थाने पहुंच गए. वहां सुबह 11 बजे से उन्होंने धरना शुरू कर दिया, जो देर शाम तक जारी रहने के बाद खत्म किया.

मोर्शी पुलिस के डीबी दल ने डोंगरयावली क्षेत्र के जुआ अड्डे पर छापा मारकर नौ आरोपियों को हिरासत में लिया था. इस कार्रवाई में लगभग 5 लाख 88 हजार रुपए की सामग्री जब्त की गई थी. हालांकि, छापेमारी के दौरान कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए भागे.

इस दौरान सूरज भागते समय ज्ञानेश्वर भोपते के खेत के कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि सूरज की मौत पुलिस के छापा मारने वाली टीम की गलती के कारण हो सकती है. मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है.

थाने में ग्रामीणों का रोष

घटना के बाद परिजन व डोंगरयावली गांव की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में मोर्शी थाने पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनका कहना है कि सूरज का शव तब तक नहीं उठाया जाएगा, जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी. थाना परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया था. पुलिस बल तैनात किया गया. एसडीपीओ उमेश पाटिल ने ग्रामवासियों से चर्चा कर उन्हें समझाया.

वर्धा-नागपुर मार्ग स्थित दत्तपुर चौक पर प्रतीकात्मक नामफलक

दत्तपुर चौक का नामकरण करें : पूर्व सैनिक पवार, के हाथों नाम फलक का उद्घाटन

वर्धा : वर्धा में प्रवेश करनेवाले वर्धा-नागपुर मार्ग पर स्थित दत्तपुर चौक को नागरिकों ने भारतरत्न आचार्य विनोबा भावे नाम देने की मांग की है. प्रतीकात्मक तौर पर नागरिकों ने फलक लगाकर अपनी मांग पुख्ता की है. इस अवसर पर नागरिकों ने पौधरोपण किया.

दत्तपुर परिसर को विनोबा भावे का नाम देने का प्रमुख कारण यहां उनका निवास, देशसेवा तथा उनके द्वारा दी गई सामाजिक शिक्षाएं हैं. दत्तपुर स्थित कुष्ठरोगी आश्रम में रहकर उन्होंने कुष्ठरोगियों की सेवा की और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का स्थान उपलब्ध कराया. इसी प्रकार दत्तपुर से सटे नालवाड़ी स्थित हरिजन बस्ती में उस समय कोई भी साफ-सफाई करने नहीं जाता था. ऐसे समय में विनोबा भावे स्वयं वहां जाकर नियमित रूप से साफ-सफाई करते थे और समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया. पूरे देश में भूदान आंदोलन के माध्यम से दलित, पिछड़े और भूमिहीन लोगों को जीवनयापन के लिए खेती की जमीन उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू की गई. इस भूदान आंदोलन का बीजारोपण भी इसी क्षेत्र में हुआ था. पवनार स्थित विनोबा भावे के आश्रम परिसर की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से हुई थी. इस क्षेत्र में विनोबा भावे के इतने बड़े योगदान को ध्यान में रखते हुए तथा कई दिनों से पवनार, नालवाड़ी, सातोडा, आलोडी और म्हसाला के नागरिकों की भावना को देखते हुए उनके पदस्पर्श से पावन हुए दत्तपुर परिसर को उनका नाम देने की मांग की गई है.

भारतरत्न आचार्य विनोबा भावे के नाम के फलक का उद्घाटन पूर्व सैनिक अभिमन्युजी पवार, प्रा. उमाकांती डुकरे और विवाद मुक्त समिति अध्यक्ष पंकज काचोले के हाथों किया गया. इस अवसर पर ग्रा.पं. सदस्य वैभव सूर्यवंशी, बंटी खडसे, प्रवीण बुराडे, नितिन निमकर, नागेश वानखेड़े, प्रतीक मांडले, संजय जिम्मेवार, सुनील कामडी, रवी मडावी, विक्रांत चौधरी, अमोल पेटकर, सचिन साठे, विजय भोयर, ज्ञानेश्वर राऊत, हरीश खडसे सहित अनेक विनोबा भावे प्रेमी उपस्थित थे.

सालों से खाली २८ प्लॉटों की जमीन होगी वापस

गड़चिरोली : गड़चिरोली औद्योगिक में लगभग 100 प्लॉटों में से 28 प्लॉट वर्षों से खाली पड़े हैं और वहां कोई उद्योग नहीं है. एमआईडीसी की सस्ती दरों पर आवंटित इन जमीनों पर कुछ धारकों ने केवल करारनामा कराकर कब्जा बना रखा है, लेकिन वास्तविक निवेश या निर्माण नहीं किया. निगम के नियमों के अनुसार प्लॉट मिलने के 2-3 वर्ष के भीतर उद्योग शुरू करना अनिवार्य है, प्लॉट धारकों नोटिस देकर आवंटन रद्द किया जा सकता है.

उद्योग विभाग ने गड़चिरोली के इन 28 प्लॉटधारकों समेत नियम तोड़ने वालों को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि जल्द अंतिम चेतावनी दी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय नए उद्यमी शिकायत करते हैं कि एमआईडीसी कार्यालय में उन्हें 'कोई खाली प्लॉट नहीं' बताकर लौटा दिया जाता है, जबकि कई प्लॉट अस्तित्व में पड़े हैं. कुछ छोटे उद्योगों ने अपनी जरूरत से कई गुना बड़ी जमीनें घेर रखी हैं, जिससे नए निवेशकों के लिए अवसर सीमित हो रहे हैं. अधिकारी बताते हैं कि नियमों के सख्ती से पालन और प्लॉटों के पुनः आवंटन से निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

बड़ा हिस्सा खर्च नहीं होने से किसान लाभ से वंचित

फलोत्पादन : मिले 1 करोड़ खर्च किए मात्र 30 लाख

वर्धा : किसानों को फलोत्पादन की ओर बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है. इसलिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता और अनुदान उपलब्ध कराती है. हालांकि, वर्धा जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वयन को ही प्रशासनिक देरी का झटका लगने की बात सामने आई है. फलोत्पादन के लिए जिले को 1 करोड़ 15.77 लाख रुपए का लक्ष्य दिया था, जबकि वास्तविक रूप से केवल 30.12 लाख रुपए ही खर्च किए गए. इससे मंजूर निधि का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो सका और कई किसान अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए.

जिले में फलोत्पादन, संरक्षित खेती और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्याज भंडारण गृह, पैक हाउस, पावर स्प्रे, प्लास्टिक मल्चिंग, ड्रैगन फ्रूट, हल्दी की खेती सहित विभिन्न घटकों के लिए अनुदान दिया जाता है. हालांकि, इन योजनाओं को लेकर प्रभावी जनजागृति, आवेदन प्रक्रिया व वास्तविक क्रियान्वयन में अपेक्षित गति नहीं होने की किसानों की शिकायत है.

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्याज भंडारण गृह के लिए 8 लाभार्थियों को 7 लाख 87,500 रुपए, ट्रैक्टर के लिए 3 लाभार्थियों को 3 लाख 50 हजार रु. तथा ड्रैगन फ्रूट के विभिन्न घटकों के लिए अनुदान दिया. ड्रैगन फ्रूट पुनर्जीवन के लिए 26 लाभार्थियों को 97,200 रु., पैक हाउस के लिए 5 लाभार्थियों को 10 लाख 44,638 रु. का अनुदान दिया. इसके अलावा पावर स्प्रे, प्लास्टिक मल्चिंग, मिर्च और हल्दी की खेती के लिए भी अनुदान दिया है. जिले के कुल निर्धारित लक्ष्य की तुलना में खर्च की राशि कम होने से योजना का अपेक्षित प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा.

प्रभारी के भरोसे विभाग

जिले में बीते चार साल से कृषि अधीक्षक स्थायी नहीं थे. प्रभारी अधिकारी के भरोसे यह विभाग था, जिससे याजनाएं प्रभावित हुई. इस संबंध में जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अरविंद उपरीकर ने बताया कि बीते मार्च महीने तक खर्च पूरा नहीं हो सका. लेकिन अगले वर्ष यह निधि खर्च की जाएगी.

३२० प्रवेश रद्द होने के बाद ईओडब्ल्यू की जांच

कॉलेज-एजेंट की भूमिका पर नजर : विद्यार्थियों के नाम पर शपथपत्र किसने दिए?

नागपुर : हिंदी भाषी अल्पसंख्यक कोटे के तहत नागपुर के चार इंजीनियरिंग कॉलेजों में हुए ३२० प्रवेश रद्द होने के बाद अब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामले की जांच शुरू कर दी है. विद्यार्थियों की शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सोमवार २४ अगस्त को बुलाया है. सोमवार को उनके बयान दर्ज किए जाएंगे. इस जांच में अब कॉलेजों के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल एजेंटों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है.

विद्यार्थियों ने शिकायत में आरोप लगाया है कि इंजीनियरिंग में प्रवेश दिलाने के नाम पर एजेंटों ने उनसे शैक्षणिक दस्तावेज लिए थे. विद्यार्थियों के अनुसार, उन्हें मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से प्रवेश दिलाने की बात कही गई थी और इसके लिए करीब डेढ़ से दो लाख रुपए तक लिए गए. बाद में कथित तौर पर उनकी जानकारी या अनुमति के बिना लिविंग सर्टिफिकेट में मातृभाषा से संबंधित जानकारी में बदलाव कर उन्हें हिंदी भाषी अल्पसंख्यक कोटे के तहत प्रवेश दिलाया गया.

टीसी में मिली अलग जानकारी

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ के दस्तावेजों की जांच के दौरान महाराष्ट्र प्रवेश नियामक प्राधिकरण (एआरए) और तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) के समक्ष विद्यार्थियों के दस्तावेजों में विसंगतियां सामने आई थीं. कुछ विद्यार्थियों के अलग-अलग टीसी में मातृभाषा संबंधी जानकारी अलग पाई गई. इसके बाद उनसे हिंदी भाषी अल्पसंख्यक होने के वैध दस्तावेज मांगे गए. सुनवाई के दौरान पात्रता साबित नहीं कर पाने पर एआरए ने ३२० प्रवेशों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया.

जवाब तलाश करेगी ईओडब्ल्यू?

जांच में यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थियों के दस्तावेजों में कथित बदलाव किस स्तर पर हुए, उनके नाम पर शपथपत्र किसने तैयार कराए और जमा किए तथा एजेंटों और कॉलेज कर्मचारियों की इसमें क्या भूमिका थी. ईओडब्ल्यू, नागपुर शहर के सहायक पुलिस निरीक्षक सुशील धोकटे की जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही इन आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होगी.

स्टाफ और बाहरी एजेंटों की कथित मिलीभगत का आरोप

ईओडब्ल्यू के २२ अगस्त के नोटिस में शिकायत में लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है. इसमें कॉलेज स्टाफ और बाहरी एजेंटों की कथित मिलीभगत से विद्यार्थियों को हिंदी भाषी अल्पसंख्यक दर्शाकर प्रवेश दिलाने तथा विद्यार्थियों को जानकारी दिए बिना उनके नाम पर शपथपत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के अनुसार, उक्त प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों को संबंधित कॉलेजों में प्रवेश दिया गया. छह महीने की निर्धारित अवधि में अल्पसंख्यक होने संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्रवेश रद्द हुए, जिससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक नुकसान की बात शिकायत में कही गई है.

झाडापापडा में महिलाओं ने किया एल्गार

शराब बिक्री के खिलाफ मुसलाधार बारिश में निकाली रैली

संवाददाता । गड़चिरोली

धानोरा तहसील के झाडापापडा गांव में अवैध शराब बिक्री बंद कराने के लिए महिलाओं ने तेज बारिश के बीच रैली निकालकर जनजागरण किया. मुक्तिपथ-शक्तिपथ संगठन की महिलाओं ने शराब विक्रेताओं को अंतिम चेतावनी देते हुए अवैध कारोबार बंद करने का आह्वान किया. साथ ही शराब बिक्री बंद नहीं होने पर पुलिस विभाग के माध्यम से कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई. गांव की महिलाएं तथा ग्रामीणों के प्रयासों से पहले ही गांव में अवैध शराब बिक्री बंद कराई गई थी. इसके बावजूद कुछ शराब विक्रेताओं द्वारा चोरी-छिपे दोबारा शराब बेचने की जानकारी सामने आई. इसके बाद गांव

संगठन की महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया. ग्रामसभा में सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव भी पारित किया गया है. इसके बावजूद कुछ विक्रेताओं द्वारा छिपकर शराब बिक्री किए जाने से महिलाओं में नाराजगी है. गांव में शराबबंदी का माहौल मजबूत करने तथा नागरिकों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बारिश के बीच रैली निकाली गई. इस दौरान ग्रामीणों ने बैठक आयोजित कर अहिंसक कार्रवाई की योजना बनाई तथा अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा की. गांव के अवैध शराब विक्रेताओं से शपथपत्र भी लिया गया. अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मुक्तिपथ के माध्यम से दुर्गम क्षेत्र के नागरिकों में जनजागृति की जा रही है. इसके मद्देनजर दुर्गम क्षेत्र के नागरिक अब शराब बिक्री के खिलाफ आगे आ रहे है. शराबबंदी के संदर्भ में प्रस्ताव पारित कर अवैध शराब बिक्रेताओं को शराब बिक्री बंद करने की चेतावनी दी जा रही है. वहीं अहिंसक कृति तथा विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से गांव से शराब को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है.

शराब बिक्री बंद होने तक पिछे नहीं हटेंगे

इस दौरान महिलाओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक गांव में शराब बिक्री पूरी तरह बंद नहीं होती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे. रैली व जनजागरण अभियान में गांव पटेल धनेश पवार, गांव पुजारी सीताराम कुदराम, सरपंच कांडेराम उसेंडी, उपसरपंच धनराज धनलिया, मुक्तिपथ-शक्तिपथ संगठन की अध्यक्ष जमुना पवार, उपाध्यक्ष धनेश्वरी पवार, सचिव प्रेमता नाईक समेत बड़ी संख्या में महिला सदस्य, मुक्तिपथ के तहसील संयोजक राहुल महाकुलकर, तहसील प्रेरक नरेश मोहुर्ले, शितल गुरनुले उपस्थित थे.

संगठन को मजबूत बनाए रखने पर जोर

संवाददाता । कुरखेडा

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, तहसील कुरखेड़ा की विभिन्न शाखाओं की ओर से कढोली में डा. नरेंद्र दाभोलकर के स्मृति दिवस के अवसर पर निर्धार दिवस मनाया गया. इस दौरान अंधश्रद्धा निर्मुलन पर मार्गदर्शन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता डा. दशरथ आड़े ने की. प्रमुख अतिथि के रूप में विठ्ठलराव कोठारे, ठाकरे, सुधा चौधरी, सुनीता तागवान, अलका बोभाटे तथा सुधा मात्तोरे उपस्थित थीं. कार्यक्रम आंदोलन गीत प्रस्तुत किया गया.

कार्यक्रम की प्रस्तावना में जिला उपाध्यक्ष डोंगरवार ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पांच प्रमुख सिद्धांतों की जानकारी देते हुए उनके महत्व पर विस्तृत मार्गदर्शन किया. प्रमुख मार्गदर्शक विठ्ठलराव कोठारे ने संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित मासिक तथा साप्ताहिक बैठकें आयोजित करने व कार्यों का उचित नियोजन करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

वहीं ठाकरे ने प्रधान सचिव के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारियों तथा विभिन्न समस्याओं का चर्चा व समन्वय के माध्यम से समाधान करने की आवश्यकता बताई. इस समय उपस्थित अन्य मान्यवरों ने अपने आसपास घटित अंधविश्वास से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की जानकारी साझा की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया. कार्यक्रम का संचालन ईश्वर चौधरी ने किया, आभार गंगाधर लोनबले ने माना. कार्यक्रम में पुराडा, कुरखेड़ा, उराडी, सोनारंगी तथा कढोली समेत विभिन्न शाखाओं के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे. सभी शाखाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया.

नए पुलिस सहायता केंद्र की जरूरत

सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने की भाकपा की मांग

संवाददाता । गडचिरोली

भामरागड़ तहसील और सीमावर्ती क्षेत्रों में आदिवासी तथा अन्य नागरिकों को नक्सली गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्गम और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में अधिक से अधिक नए पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं. साथ ही इंद्रावती नदी किनारे और सीमावर्ती क्षेत्रों में आदिवासियों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गश्त बढ़ाई जाए, ऐसी मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है.

भाकपा ने 'माओवादियों के फिर से संगठित होने के प्रयास' संबंधी खबर का हवाला देते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ की दिशा से इंद्रावती नदी पार कर बाहरी माओवादी दुर्गम गांवों में प्रवेश करने की घटनाएं सामने आ रही हैं. बंदूक के बल पर स्थानीय आदिवासी नागरिकों को विभिन्न

पुलिस सहायता केंद्रों से विकास को भी गति

ज्ञापन में कहा गया है कि, जिन क्षेत्रों में शासन की ओर से पुलिस सहायता केंद्र शुरू किए जाते हैं, वहां सड़क, बिजली, एसटी बस सेवा, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में भी मदद मिलती है. इसलिए पुलिस सहायता केंद्र केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों के विकास के केंद्र भी बन सकते हैं. इसी दृष्टि से भामरागड़ तहसील के अतिसंवेदनशील और दुर्गम क्षेत्रों में अधिक से अधिक पुलिस सहायता केंद्र शुरू करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग ज्ञापन में की गई है.

कार्य करने अथवा माओवादियों को आश्रय देने के लिए मजबूर किए जाने की आशंका जताई गई है. भाकपा ने मांग की है कि, भय और दबाव के कारण माओवादियों का सहयोग करने के लिए मजबूर होने वाले निर्दोष आदिवासी नागरिकों के खिलाफ बाद में पुलिस कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. प्रशासन को ऐसे नागरिकों के प्रति संरक्षण और सहयोग की भूमिका निभानी चाहिए.

शहर की सड़कों पर बिछा केबल का जाल

संवाददाता । गड़चिरोली

शहर स्वच्छ, सुंदर बनाने के लिये प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है. लेकिन दूसरी ओर व्यवसाय करनेवाले कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करने के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गड़चिरोली शहर में केबल को जाल फैला है. वहीं अनेक जगह पर वायर झुके होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है. पहले ही गडचिरोली शहर की अंतर्गत सडकों की चौडाई कम है. ऐसे में बिजली खंभों पर केबल के वायर है जो अनेक जगह पर अत्यधिक झुके हुए दिखाई दे रहे है. लेकिन इस मामले की ओर संबंधित विभाग अनदेखी कर रहा है.

ऐसे में केबल टूटकर दुर्घटना की संभावना रहती है. शहर के फुले वार्ड में अनेक जगह पर बिजली खंभों से गली-गली में टीवी की केबल लाईन बिछाई गयी है. इसके अलावा शहर के गोकुलगनर, रामनगर, विवेकानंदनगर, लांझेडा समेत अन्य वाडों में भी बिजली खंभों पर केबल लाईन बिछाई गयी है. इनमें अनेक जगहों पर यह केवल झुके हुए अवस्था में दिखाई दे रहे है. ऐसे में भारी वाहन आने पर लकड़ी से केबल को उपर उठाना पड़ता है. कम उंचाईवाले केबल के चलते दुर्घटना के खतरे को भांपते हुए वाहन चालकों को वाहन चलाने पड़ रहे है. जिससे संबंधित विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान दे. ऐसी मांग की जा रही है.

बदलता मौसम व तेज गर्मी का असर किसानों पर संकट

मृग बहार के संतरे की फलझड़ शुरू

संवाददाता । कारंजा-घाडगे

विदर्भ की 'संतरा पंढरी' के रूप में पहचान रखने वाले कारंजा तहसील में मृग बहार के संतरे की बड़े पैमाने पर फलझड़ शुरू हो गई है. पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव, तेज गर्मी और बारिश में लंबा खंड पड़ने से संतरे के पेड़ों पर पानी का तनाव बढ़ गया है. इससे नींबू के आकार तथा उससे बड़े फल पीले होकर जमीन पर गिर रहे हैं. खेतों में पेड़ों के नीचे हरे-पीले फलों का ढेर दिखाई दे रहा है, जिससे संतरा उत्पादकों में चिंता का माहौल है.

शुरुआत में अच्छी बारिश होने से संतरे की बागों में मृग बहार संतोषजनक आया था. फलधारणा भी अच्छी होने से किसानों को इस वर्ष बेहतर उत्पादन की उम्मीद थी. इस उम्मीद में किसानों ने कर्ज और उधारी लेकर खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व,

मशागत तथा बागों की देखभाल पर लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन फल बढ़ने की अवस्था में ही बड़े पैमाने पर फलझड़ शुरू होने से उत्पादन में 50 से 60 प्रतिशत तक कमी आने की आशंका जताई जा रही है. लगातार बारिश नहीं होने से जमीन में नमी की कमी और बढ़ते तापमान के कारण फलों के डंठल कमजोर होने की बात किसानों द्वारा कही जा रही है.

कुछ क्षेत्रों में जलनिकासी की समस्या से भी पेड़ों की जड़ों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. संतरा कारंजा तहसील के किसानों की प्रमुख नकदी फसल है. किसानों ने कृषि विभाग से तत्काल बागों का सर्वेक्षण कर तकनीकी मार्गदर्शन देने तथा राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त पंचनामा कर प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

बेलोरा स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर नाराजगी

संवाददाता / आष्टी-शहीद

बेलोरा बु. स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में कार्यरत एएनएम के कामकाज और उनके पति के कथित हस्तक्षेप को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एएनएम के पति द्वारा गांव के नागरिकों के साथ कथित तौर पर दबंगई की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है.

साथ ही छोटे बच्चों के साथ भी अभद्र भाषा में गालीगलौज किए जाने का आरोप लगाया गया है. ग्रामीणों का दावा है कि इस संबंध में ऑडियो क्लिप भी उनके पास उपलब्ध है. ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र में एएनएम के पति किस अधिकार के तहत हस्तक्षेप कर रहे हैं. इसी को लेकर ग्रामीणों में 'बिन वेतन फुल अधिकारी की चर्चा भी हो रही है. ग्रामीणों के अनुसार, संबंधित एएनएम के कामकाज को लेकर पहले भी नाराजगी व्यक्त की जा चुकी है. वर्तमान में नागरिकों के साथ कथित तौर पर किए जा रहे अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार को लेकर शिकायतें सामने आयी हैं. स्वास्थ्य सेवा के लिए उपकेंद्र में आने वाले नागरिकों से सम्मानपूर्वक संवाद करने के

बजाय कथित रूप से रूखे तरीके से बात करने, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और नागरिकों की शिकायतों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए गए हैं.

गांव के अधिकांश नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी उपकेंद्र पर निर्भर हैं. ऐसे में स्वास्थ्य सेवा लेने आने वाले नागरिकों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किए जाने को ग्रामीणों ने गंभीर मामला बताया है. ग्रामीणों ने संबंधित एएनएम का तबादला करने की मांग की है. इस संबंध में तहसीलदार आष्टी, पंचायत समिति आष्टी के गट विकास अधिकारी तथा तालुका स्वास्थ्य अधिकारी आष्टी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है. अब प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, इस ओर बेलोरा बु. के ग्रामीणों का ध्यान लगा हुआ है.

मूसलाधार बारिश से आयी बाढ़, वाहनों की लंबी कतारें लगी

भीमपुर राजमार्ग का यातायात 7 घंटे ठप

संवाददाता । कोरची

गड़चिरोली जिले के अंतिम छोर पर स्थित कोरची तहसील में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. शनिवार आधी रात से शुरू हुई तेज बारिश के चलते कोरची-भीमपुर नाले में बाढ़ आ गई. नाले का पानी पुल तथा सड़क के ऊपर से बहने के कारण कोरची-भीमपुर-बोटेकसा राज्य मार्ग पर करीब सात घंटे तक यातायात पूरी तरह बंद रहरी. कोरची-भीमपुर-बोटेकसा राज्य मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो आगे छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ता है. इसके कारण इस मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में हल्के और भारी वाहनों का आवागमन होता है. हालांकि, मूसलाधार बारिश के कारण भीमपुर नाले के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो गई और पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यातायात बंद कर

दिया. मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पानी कम होने तक वाहन चालकों को सड़क पर ही इंतजार करना पड़ा. इस दौरान यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कोरची पुलिस ने नाले के पास कड़ा बंदोबस्त तैनात किया था. पुलिस ने नागरिक तथा वाहन चालकों से अपील की कि पुल के ऊपर से तेज बहाव में पानी गुजरने के दौरान जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने का प्रयास न करें. करीब सात घंटे बाद नाले का पानी कम होने पर कोरची-भीमपुर राज्य मार्ग पर यातायात फिर से शुरू किया गई. इससे वाहन चालकों को राहत मिली.

मूसलाधार बारिश के कारण कोरची-बेतकाठी मार्ग पर स्थित गुटेकसा नाला भी उफान पर आ गया. करीब चार घंटे तक नाले का पानी सड़क के ऊपर से बहता रहा. इसके चलते इस मार्ग पर भी कुछ समय के लिए यातायात बंद रखना पड़ा. लगातार बारिश के कारण गुटेकसा तथ्क्षा भीमपुर नाले के आसपास स्थित खेतों में पानी भरने की आशंका बढ़ गई है. इससे किसानों में चिंता का माहौल है. प्रशासन और पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मूसलाधार बारिश के दौरान नदी-नालों, पुलों और निचले इलाकों से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतें. पानी का तेज बहाव जारी रहने पर सड़क या पुल पार करने का जोखिम न उठाएं.

सोने की चेन छीनने वाला आरोपी अरेस्ट

संवाददाता / हिंगनघाट

शहर में मॉर्निंग वॉक पर निकली 74 वर्षीय वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हुए आरोपी को हिंगनघाट पुलिस ने चंद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, कपड़े तथा चोरी की सोने की चेन को गलाकर बनाए गए सोने के लगड़ सहित कुल 2 लाख 64 हजार 400 रुपए का माल जब्त किया है. आरोपी का नाम जनरलसिंग उर्फ मन्नुसिंग रामसिंग टाक (40), निवासी समतानगर, नेरी, दुर्गापुर,

चंद्रपुर बताया गया.

9 अगस्त को नेहरु वार्ड निवासी मनोज रमेशचंद्र सिंघवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उनकी मां इंदुमती सिंघवी (74) सुबह करीब 6.30 बजे कारंजा चौक से तुकडोजी चौक रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रही थीं. इसी दौरान घटना सामने आयी. जांच के दौरान टीम ने आसपास के गांवों तथा शहर से गुजरने वाले हाईवे मार्गों के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की. इसी दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली.

पुलिस ने चंद्रपुर पहुंचकर रिकॉर्ड पर मौजूद आरोपी जनरलसिंग उर्फ मन्नुसिंग रामसिंग टाक को हिरासत में लिया. आरोपी ने बताया कि उसने चोरी की सोने की चेन चंद्रपुर के एक सोनार के यहां बेच दी थी. आरोपी से दोपहिया क्रमांक सीजी 07 एलजेड 7170, सोनार के पास से चोरी की चेन को गलाकर तैयार किया गया 16.940 ग्राम सोने का लगड़, कुल 2 लाख 64 हजार 400 रुपए का माल जब्त कर लिया.

तेलंगाना के चावल की अवैध बिक्री

गड़चिरोली : तेलंगाना के सरकारी राशन दुकानों से गरीबों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले चावल को महाराष्ट्र में लाकर कथित रूप से अवैध तरीके से बेचने का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. नागरिकों का आरोप है कि तेलंगाना का कथित कुख्यात चावल तस्कर 'विरेन' सिरोंचा सीमा क्षेत्र में फिर सक्रिय हो गया है. सिरोंचा आसरअल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पिछले 10 से 12 वर्षों से इस तरह का अवैध कारोबार चलने की शिकायतें की जा रही हैं. तहसील कार्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह गतिविधियां चलने के बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है. बताया जाता है कि तेलंगाना से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में चावल ऑटो, पिकअप, ट्रक, ट्रैक्टर सहित विभिन्न वाहनों से सिरोंचा लाया जाता है. बाजार में बारीक चावल की अधिक मांग होने के कारण हाल के दिनों में इस कारोबार को कथित रूप से और बढ़ावा मिलने की चर्चा है. आरोप है कि सिरोंचा स्थित कथित अवैध भंडारण केंद्र में चावल को अलग-अलग बोरियों में भरकर नए ब्रांड के नाम से गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में भेजा जाता है. इससे सरकारी राशन व्यवस्था के चावल की अवैध बिक्री और उसके स्रोत को छिपाने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इस कथित कारोबार का प्रमुख केंद्र सिरोंचा आसरअल्ली मार्ग पर सर्वे नंबर 71 की वनभूमि में होने का आरोप है. यहां टीन के शेड, गोदाम, मजदूरों के लिए कमरे तथा अन्य निर्माण किए जाने की बात नागरिकों ने कही है. इस पूरे अवैध कारोबार का मुख्य संचालक 'विरेन' होने का आरोप लगाया गया है. नागरिकों के अनुसार, वह अपने साथियों के साथ गोदाम परिसर में रहता है. पिछले कई वर्षों से यह गतिविधि जारी होने के बावजूद कार्रवाई के अधिकार क्षेत्र को लेकर विभिन्न विभागों में कथित रूप से असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

सोयाबीन, कपास पर कीट-रोगों का प्रकोप

लगातार बादलों से फसलों पर विपरित असर

संवाददाता / वर्धा

जिले में इस वर्ष खरीफ सीजन में 1.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन और 2.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई की गई है. वर्तमान में दोनों फसलें वृद्धि की अवस्था में हैं, लेकिन इन पर विभिन्न कीट-रोगों का प्रकोप दिखाई देने लगा है. पहले से ही बारिश में लगातार खंड पड़ने से किसान परेशान हैं. ऐसे में अब सोयाबीन और कपास पर कीटों का प्रकोप बढ़ने से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

जिले में जून से अब तक 446.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इस वर्ष मानसून की शुरुआत में बारिश में देरी होने के कारण बुआई का काम प्रभावित हुआ था. बाद में बुआई के अनुकूल बारिश होने पर किसानों ने तेजी से खरीफ फसलों की बुआई पूरी की. जिले में इस खरीफ सीजन में कुल 4. 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुआई की गई है. बारिश में लगातार खंड पड़ने के कारण अंकुरित और वृद्धि की अवस्था में पहुंच चुकी फसलों को बचाए रखने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. वहीं, पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार बादल छाए रहने से फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. इसी बीच सोयाबीन और कपास पर कीटों का प्रकोप भी दिखाई देने लगा है. जिले में इस वर्ष 1,19,626.70 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई हुई है. अधिकांश क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 1 से 1.5 फीट तक बढ़ चुकी है और फिलहाल फूल आने तथा वृद्धि की अवस्था में है. इस फसल पर कुछ क्षेत्रों में कम मात्रा में चक्रभृंग, तना मक्खी और तंबाकू की पत्तियां खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है. वहीं, बारिश में खंड पड़ने के कारण सोयाबीन में फूलों के फलियों में परिवर्तित होने की दर भी कम दिखाई दे रही है. इससे उत्पादन को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है.

कपास पर माहू, तैला और सफेद मक्खी

जिले में 2,31,961.56 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई की गई है. वर्तमान में कपास की फसल वृद्धि की अवस्था में है और अधिकांश क्षेत्रों में पौधे 1.5 से 2 फीट तक ऊंचे हो चुके हैं. कुछ स्थानों पर कपास में कलियां और फूल आने की अवस्था भी शुरू हो गई है. इसी दौरान कुछ क्षेत्रों में कपास की फसल पर माहू, तैला और सफेद मक्खी का हल्का प्रकोप दिखाई दे रहा है. इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

धादरी-उमरी में जंगली सूअरों का आतंक

बार-बार हो रहे हमलों से कई घायल, स्थायी समाधान की मांग

संवाददाता / तिरोड़ा

तहसील के धादरी-उमरी क्षेत्र में जंगली सूअरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगली सूअरों के बार-बार हो रहे हमलों से किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा का गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल प्रभावी एवं स्थायी उपाययोजना करने की मांग की है।

रविवार, 23 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे खेत में गए महिपाल शेंडे (61), निवासी धादरी और वामन भालधरे (57), निवासी तिरोड़ा पर जंगली सूअरों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार जारी है।इससे पहले भी धादरी-उमरी क्षेत्र में जंगली सूअरों द्वारा किसानों एवं ग्रामीणों पर हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विशेष रूप से 13 अगस्त को एक ही दिन में जंगली सूअरों ने छह लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लगातार हो रहे हमलों के कारण किसान खेतों में जाने से भी डर रहे हैं।

जंगली सूअरों के बढ़ते उपद्रव की सूचना वन विभाग को कई बार दी गई थी। इसके बाद वनरक्षक चंद्रकुमार पारधी के नेतृत्व में करीब 10 वनकर्मियों ने धादरी-उमरी क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाया। जंगली सूअरों को पकड़ने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन अधिकांश जंगली सूअर भागने में सफल रहे। अभियान के दौरान केवल एक जंगली सूअर का बच्चा पकड़ा गया, जिसे बाद में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया।वर्तमान में खरीफ का मौसम चल रहा है और खेतों में धान की फसल की देखभाल, छिड़काव, निराई-गुड़ाई सहित विभिन्न कृषि कार्य तेजी से चल रहे हैं। लेकिन जंगली सूअरों के डर के कारण कई किसान खेतों में जाने से बच रहे हैं, जिससे कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वन विभाग की ओर से गंभीर रूप से घायल लोगों को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी गई है। हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है। जंगली सूअरों के लगातार बढ़ते हमलों पर रोक लगाने के लिए ठोस एवं स्थायी समाधान आवश्यक है। ग्रामीणों ने शासन एवं वन विभाग से धादरी-उमरी क्षेत्र में तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर किसानों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

सुरेश ठाकरे ने दलित बस्ती में दो बोरवेल करवाकर निभाया वादा

संवाददाता / डोंगरगांव

समीपस्थ ग्राम पंचायत डोंगरगांव के उपसरपंच सुरेश ठाकरे ने दलित बस्ती स्थित मातोश्री रमाबाई आंबेडकर वार्ड में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या को दूर करने के लिए किए गए अपने वादे को पूरा कर दिया है। वार्ड में पानी की टंचाई को देखते हुए उन्होंने वर्ष २०२४-२५ से लगातार शासन स्तर पर पाठपुरावा करते हुए समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए।

उपसरपंच सुरेश ठाकरे के प्रयासों से वर्ष २०२६ में रमाबाई आंबेडकर वार्ड के लिए पानी टंचाई निवारण योजना के अंतर्गत दो बोरवेल मंजूर कराए गए। इनमें से एक बोरवेल ग्राम पंचायत के पास स्थित दुर्गा मंदिर के सामने तथा दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता राजू बारसागड़े के घर के सामने खुदवाया गया है।

दोनों बोरवेल के निर्माण से वार्ड में पानी की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे वार्डवासियों ने बोरवेल मंजूर करवाकर उसे पूरा कराने के लिए उपसरपंच सुरेश ठाकरे का अभिनंदन किया और उनके प्रयासों की सराहना की। वार्डवासियों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए इसी तरह निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे।

भू-माफियाओं की गुंडागर्दी; अनिकेत जैन से मारपीट

भूमाफिया व गुंड प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ मकोका कानून के तहत कार्रवाई करें

संवाददाता / आमगांव

आमगांव के संतोष धूलचंद जैन व उनके परिवार के स्वामित्व वाली गट क्रमांक 460-अ में 4 हेक्टेयर आर जी जमीन है। इस जमीन पर कुछ भू-माफियाओं ने कब्जा करने का प्रयास शुरू किया है। इसी के चलते गुंड प्रवृत्ति का परिचय देते हुए अनिकेत जैन के साथ तथाकथित भू-माफियाओं द्वारा जमकर मारपीट की गई। यह घटना 21 अगस्त की है और आमगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि, भू माफिया गुंडे के पास पुलिस की स्टिक भी थीं। इसलिए पुलिस की स्टिक गुंडे के पास कैसे आईं यह सवाल भी उठाया जा रहा है।

विस्तार से ऐसा है कि, आमगांव के संतोष धूलचंद जैन व परिवार की स्वामित्व हक वाली गट क्रमांक 460-अ में 4 हेक्टेयर आर जमीन है। इसमें से एक हेक्टेयर जमीन गुलाब रफिक बब्बू सय्यद को बेची गई है। शेष तीन हेक्टेयर जमीन जैन परिवार के स्वामित्व की है। बताया गया कि जैन परिवार के पास जमीन के सरकारी अभिलेख, दस्तावेज, मापी के कागजात, 'क' प्रति व नक्शे उपलब्ध हैं। लेकिन, जमीन से सटे गट क्रमांक 459 की अकृषक अनुमति के दौरान विसंगति दिखाकर जैन के स्वामित्व हक वाली जमीन पर कब्जा करने का प्रयास भू-माफियाओं ने किया। इसी में जैन द्वारा लगाए गए खंभे गिराकर तोड़फोड़ की गई। इस बीच इन बातों का विरोध करने पर भू-माफियाओं ने गुंडागर्दी का परिचय देते हुए अनिकेत जैन के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना की शिकायत आमगांव पुलिस थाने में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

916 घंटागाड़ियां होकर भी कचरे के ढेर

868 गांवों में व्यवस्था बेहाल, कागजों तक सीमित घंटागाड़ी सेवा

संवाददाता / गोंदिया

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संकलन के लिए बड़ी संख्या में घंटागाड़ियां उपलब्ध होने के बावजूद ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति गंभीर बनी हुई है. जिले की 548 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 868 गांव आते हैं और कचरा संकलन के लिए 916 घंटागाड़ियां उपलब्ध हैं. इसके बावजूद कई गांवों में नियमित कचरा संकलन नहीं होने से सड़क किनारे, मैदानों और खाली जगहों पर कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं. सभी गांवों में

कचरा उठाने के लिए घंटागाड़ी की सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों को कचरा कहां डालना है, इसकी समस्या नहीं होनी चाहिए. लेकिन कई गांवों में घंटागाड़ियां नियमित रूप से नहीं पहुंच रही हैं. इसके चलते नागरिक सड़क किनारे, खाली जगहों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने को मजबूर हैं इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अस्वच्छता का चित्र दिखाई दे रहा है. कुछ ग्राम पंचायतों में ठोस कचरा प्रबंधन प्रकल्प शुरू हैं, लेकिन कई ग्राम पंचायतों के पास अब तक कचरा मैदान अथवा कचरे के वैज्ञानिक निपटारे की व्यवस्था नहीं है. परिणामस्वरूप एकत्रित कचरा गांव के बाहर खुले स्थानों पर फेंका जा रहा है. कुछ स्थानों पर कचरे को जलाने से धुआं फैल रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. कचरे की दुर्गंध से भी नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

चिचगड-डोंगरगाव सड़क का काम तीन साल से अटका

9 ग्राम पंचायतों की जनता की जान सांसत में !

संवाददाता / देवरी

तहसील के चिचगड-डोंगरगाव मुख्य सड़क की वर्तमान में गड्ढों के जाल में फंस गई है. पिछले तीन वर्षों से उक्त सड़क का काम अटका होने से समस्या और भी बढ़ गई है. इसी गड्ढों भरी सड़क से 9 ग्राम पंचायतों के नागरिकों को जान हथेली पर रखकर यात्रा करनी पड़ रही है. इस प्रकार के कारण प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर रोष व्यक्त किया जा रहा है. इस ओर ध्यान देकर सड़क तैयार की जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी ग्रामीणों ने दी है.

प्रशासन की अनदेखी के कारण चिचगड-डोंगरगाव मुख्य सड़क की दुर्दशा हो गई है. गड्ढों भरा मार्ग यातायात के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. इस मार्ग की दुर्दशा होने से कुल 9 ग्राम पंचायतों के नागरिकों की जान सांसत में आ गई है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और बारिश का पानी जमा रहता है. ऐसे में गड्ढों का अंदाजा नहीं लगने से वाहन चालकों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो यह यात्रा अक्षरशः जानलेवा साबित हो रही है. इस सड़क के काम की वर्क ऑर्डर 2023 में मंजूर हुई. लेकिन पूरे तीन साल का समय बीत जाने के बावजूद काम पूरा नहीं हुआ है. उल्टे, मई 2026 में किया गया कंक्रीट का काम घटिया दर्जे का होने का आरोप नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है. इस घटिया काम के कारण सड़क की स्थिति और भी बदतर हो गई है. इससे ग्रामीणों में रोष पैदा हो गया है. प्रशासन व जनप्रतिनिधि तुरंत इस ओर ध्यान देकर चिचगड से डोंगरगाव सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण करें, काम होने तक गड्ढों को भरने की मांग 9 गांवों के नागरिकों ने की है. अन्यथा सड़क पर उतरकर तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसी चेतावनी भी दी गई है.

मार्ग के मजबूतीकरण व चौड़ाईकरण की मांग

संवाददाता / सालेकसा

आमगांव से सालेकसा-चांदसूरज तक जाने वाले राज्य मार्ग क्रमांक 335 के मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण एवं चौड़ाईकरण की मांग को लेकर सांसद प्रफुल्ल पटेल व सांसद राजेंद्र जैन को ज्ञापन सौंपा गया.

ज्ञापन में बताया गया है कि यह मार्ग महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है.

तहसील में कचारगढ़ देवस्थान, हाजराफॉल, पुजारीटोला बांध समेत कई पर्यटन स्थल हैं. सालेकसा प्रमुख व्यावसायिक केंद्र होने के कारण इस मार्ग पर रोजाना बड़ी संख्या में नागरिक, विद्यार्थी एवं कर्मचारियों का आवागमन होता है. मार्ग की बार-बार सिर्फ मरम्मत की जा रही है, जिससे जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं. इसका सबसे अधिक असर दोपहिया वाहन चालकों को हो रहा है. विद्यार्थी व कर्मचारियों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

चारपहिया वाहन चालकों को भी खराब सड़क के कारण दिक्कतें हो रही हैं. बढ़ते यातायात को देखते हुए सड़क का चौड़ाईकरण भी आवश्यक बताया गया. ज्ञापन सौंपते समय राकांपा तहसील अध्यक्ष डॉ. अजय उमाटे, शहर अध्यक्ष ब्रजभूषण बैस, जिला महासचिव डॉ. हीरालाल साठवणे, तहसील युवक अध्यक्ष बाजीराव तरोने, राजेश डोंगरे, रघुदास नागपुरे, ओमप्रकाश लिल्हारे, बबलू, ऋषि बैस आदि उपस्थित थे.

अलमारी में रखे सोने के आभूषण चोरी

गोंदिया : गोरेगांव थाने के तहत पाथरी निवासी फिर्यादी गुनीराम नैतराम सोनवाने (31) के घर के लोहे की अलमारी में रखे 24 हजार रु. कीमत के सोने के आभूषण अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया. फिर्यादी की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार देवेंद्र काटेंगे कर रहे हैं.

आंबेडकर प्रतिमा के समक्ष संदिग्ध कृत्य से आक्रोश

बौद्ध उपासक-उपासिकाओं ने निकाला शांतिपूर्ण मार्च, सात दिनों में जांच की मांग

संवाददाता / तिरोड़ा

तालुका के वड़ेगांव में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कथित रूप से अपमानजनक एवं संदिग्ध कृत्य किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से बौद्ध उपासक-उपासिकाओं तथा आंबेडकरवादी समाज में नाराजगी का माहौल है। नागरिकों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

घटना के विरोध में बौद्ध उपासक-उपासिकाओं एवं आंबेडकरवादी नागरिकों की ओर से शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। मार्च के बाद प्रशासन को निवेदन सौंपकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की गई। निवेदन में कहा गया कि घटनास्थल पर उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाए। जांच के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा परिसर में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से सात दिनों के भीतर जांच पूरी कर ठोस निष्कर्ष सामने लाने की मांग की है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जांच अथवा कार्रवाई नहीं होने पर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान नागरिकों ने प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ मामले की जांच कर सत्य सामने लाने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की अपेक्षा व्यक्त की।

सेवा सहकारी संस्थाओं की समस्याओं पर हुआ मंथन

किसानों के हित में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर दिया जोर

संवाददाता / तिरोड़ा

स्थित प्रेम बंधन लॉन में रविवार को सेवा सहकारी संस्थाओं के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं संचालक मंडल के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, किसानों के हित तथा सेवा सहकारी संस्थाओं के समक्ष उत्पन्न हो रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. प्रशांत पडोळे, तिरोड़ा-

गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़, सहकार जिला आघाड़ी के अध्यक्ष राधेलालजी पटले तथा सेवा सहकारी संस्था के वरिष्ठ सदस्य शिशुपाल पटले सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सहकारिता क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, संस्थाओं की विभिन्न समस्याओं तथा किसानों को अधिक प्रभावी एवं बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया गया। तिरोड़ा तहसील की विभिन्न सेवा सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक मंडल के सदस्यों ने बैठक में सक्रिय सहभागिता दर्ज कराते हुए अपने विचार एवं समस्याएं रखीं। कार्यक्रम की प्रस्तावना कृषि उपज बाजार समिति के संचालक रमेश टेंभरे ने की।

इस दौरान बाजार समिति के संचालक ओम पटले, लक्ष्मीनारायणजी दुबे, मदन पटले, अनिल भगत, नगर परिषद सदस्य पी.आर. पारधी, पूर्व सभापति वाई.टी. कटरे, रमेशजी पटले, शिशुपालजी पटले, गजानन बारापात्रे तथा बाबलदास रामटेके सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सरपंच हितेंद्र बावने ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन ओम पटले ने किया। सेवा सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उत्स्फूर्त सहभागिता के चलते बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

साखरीटोला-सातगाव मार्गावरील खड्डे जीवघेणे

जर्जर पुलामुळे वाढला वाहतुकीचा अतिरिक्त भार

संवाददाता / सालेकसा

तालु तालुक्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या साखरीटोला ते सातगाव, गांधीटोला, तिरखेडी मार्गे तालुका मुख्यालयाकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे संपूर्ण रस्ता खड्यांच्या जाळ्यात अडकला असून दररोज हजारो नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत असून नागरिक व प्रवाशांचा जीव टांगणीला आला आहे.

मुख्य आमगाव-सालेकसा मार्गावरील वाघनदीचा पूल अत्यंत जर्जर आणि धोकादायक झाल्याने, त्या मार्गावरील सर्व अवजड वाहतूक साखरीटोला मार्गे वळवण्यात आली आहे. या अनियंत्रित आणि जड वाहतुकीच्या अतिरिक्त भारामुळे आधीच खराब झालेल्या साखरीटोला सालेकसा रस्त्याचे

अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. तसेच रस्त्याकडेला योग्य नाल्यांची सोय नसल्याने पावसाचे पाणी थेट रस्त्यावरच साचत आहे. पाण्यामुळे खड्यांचा अंदाज न आल्याने या मार्गावर अपघातांचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. या मार्गावरून दररोज शाळकरी मुले, शेतकरी, शेतक महिला आणि हजारो चाकरमानी प्रवास करतात, ज्यांच्या वाहनांचे अतोनात नुकसान होत आहे.

साखरीटोला येथील संगीताताई शहारे यांच्या घरापासून ते गंगा किराणा स्टोअर्स, दोन्हीडे कृषी केंद्र आणि बोहरे क्लॉथ ते चौरस्त्यापर्यंतचा रस्ता पूर्णपणे खड्?यात गेला आहे. रस्त्यावर पडलेल्या प्रचंड मोठ्या आडव्या-उभ्या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचल्याने वाहनधारकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यागंभीर समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत परिसरातील ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. साखरीटोला, सातगाव, गांधीटोला आणि तिरखेडी मार्गावरील खड्डे तातडीने बुजवून रस्त्याची कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्यात यावी, जर्जर रस्त्यावरून होणाऱ्या अनियंत्रित अवजड वाहतुकीवर तातडीने निर्बंध लावावेत, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

मुंडीपार एमआईडीसी की कावड़ यात्रा को मिला उत्साहपूर्ण प्रतिसाद

संवाददाता / डोंगरगांव

समीपस्थ ग्राम मुंडीपार (एमआईडीसी) में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता देबीलाल शुलाखे के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभाग लिया।

कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह फल, फ्रूट एवं अल्पाहार की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था मुंडीपार एमआईडीसी की सरपंच सौ. भुमेश्वरीताई देबीलाल शुलाखे की ओर से की गई थी। कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। आयोजन को ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं का अच्छा-खासा प्रतिसाद मिला।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक चंद्रकांत खंडेलवाल द्वारा भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरूनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर गुरूनानक वार्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.
संपादक :- चंद्रकात खंडेलवाल, पी.आर.पी एक्ट के तहत जिम्मेदार *